RAJYA SABHA

Friday, the 15*th March*, 2002/24 *Phalguna*, 1923 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock,

MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Installed Production Capacity of Fertilizer Plants

*181. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) the number of fertilizer/urea plants set up during the Ninth Five Year Plan period and those proposed to be set up during the Tenth Five Year Plan, State-wise and location-wise;

(b) the installed production capacity of each of aforesaid units; and

(c) by when, their commercial production is expected to be started?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKHDEV SINGH DHINDSA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The details of major fertilizer projects in India commissioned during ninth plan period and under implementation at present, indicating their additional production capacity, location, month/year of commissioning etc., are given in the enclosed statement-I (*See* below).

There is no decision on any fresh investment for a new unit under public/co-operative sector. Setting up of fertilizer plants in the private sector is not subject to any licensing requirements.

Statement-I

Major fertilizer projects set up during the ninth Plan Period

S.No.	Name	Location	Product	Additional Capacity (in lakh TPA)	Month/Year of Commissioning
1	2	3	4	5	6
		Already Commissioned			
1.	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., Kalol Expansion Project	Kalol, Gujarat	Urea	1.50	August 97
2.	Indian Farmers Fertiliser Cooperative Ltd., Phulpur Expansion Project	Phulpur, UP	Urea	7.26	December 97
3.	Madras Fertilizers limited, Revamp Project	Chennai, Tamil-Nadu	Urea NPK	0.76 1.84	March 98
4.	Nagarjuna Fertilizers & Chemicals Ltd., Kakinada Expansion Project	Kakinada, AP	Urea	4.95	March 98
5.	Zuari Agro Chemicals Ltd., DAP Expansion Project	Goa	DAP NPK	1.80 1.50	June 98 November 98
6.	Kandla Expansion Project of IFFCO	Kandla, Gujarat	DAP NPK	3.70 2.27	August 99
7.	Hind Lever Chemicals Ltd.	Haldia, West Bengal	DAP / NPK	4.00	April 99
8.	Expansion project of Chambal Fertilizers and Chemicals Ltd., (Ph-II)	Gadepan, Rajasthan	Urea	7.75	October 99
9	Indo Gulf Corporation Ltd., (new project)	Dahej, Gujarat	DAP	4.00	October 2000
10.	Coromandel Fertilizers Ltd., (NPK expansion project)	Vyzag, A.P.	NPK	1.25	July 2000
11.	National Fertilizers Ltd. (NFL) (urea plant expansion project)	Nangal, Punjab	Urea	1.48	February 2001

1	2	3	4	5	6
12.	Oswal Chemicals & Fertilizers Ltd. (New)	Paradeep, Orissa	DAP NPK NP	15.00 3.20 1.00	April 2001
13.	Godavari Fertilizers & Chemicals Ltd. (GFCL)	Kakinada, A.P.	DAP	2.8	Sept. 2001
		Under Implementation			
1.	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd., (DAP Expansion Project)	Sikka, Gujarat	DAP	3.96	April 2002
2.	Revamp of Namrup Plants of Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFC)	Namrup, Assam	Urea	3.80	Oct. 2002

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया है और उसमें से जो प्रश्न मुझे पूछना है वह इस प्रकार है कि फर्टिलाइज़र प्लांट्स जो हमारे देश में लगे या चले, उनका एक्सपेंशन हुआ, उनकी कैपेसिटी निर्धारित हुई, लेकिन फर्टिलाइजर प्लांट्स की परफार्मेंस के बारे में स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसको देखने से यह स्पष्ट लगता है कि जो प्लांट्स लगाए गए , वे अपनी कैपेसिटी पर काम नहीं कर पाए। उनका एक्सपेंशन किया गया तो एक्सपेंशन करते समय कॉस्ट ओवररन हुआ, टाइम ओवररन हुआ और उसी के कारण प्लांट्स की जो कॉस्ट है तथा जो मैटीरियल या फर्टिलाइजर प्रोड्यूस किया जाता है, स्वाभाविक रूप से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर में कहना चाहूंगा, स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जो वर्णित किया है वह यह है कि एचएफसी का नामरूप प्लांट जो था, उसका एक्सपेंशन प्रोग्राम 234 करोड़ रुपये का तय किया गया था और 1998 में उसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद उसके एक्सपेंशन का प्रोग्राम इन्कम्पलीट रहा, 2000 तक 63 परसेंट हुआ। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि नामरूप के एक्सपेंशन को अगर कम्पलीट करना है तो उस एक्सपेंशन के कम्पलीशन के लिए उनको 509 करोड़ रुपया चाहिए। सभापति महोदय, टाइम पर जब कोई काम पूरा नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से उसकी कास्ट बढ़ती है। जब कास्ट बढ़ जाती है तो जो मैटीरियल प्रोड्यूस किया जाएगा उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक्सपेंशन प्रोग्राम्ज या कमीशनिंग प्रोग्राम्ज डिले हुए और डिले होने के कारण उनमें जो कास्ट ओवररन और टाइम ओवररन हुआ और उसके कारण जो मैटीरियल प्रोड्यूस हुआ उसकी जो कॉस्ट बढ़ी और उनके कारण जो उनको नुकसान हुआ क्या इस संबंध में उन्होंने डिटेल्ड जानकारी इकट्ठी की है, यह मेरे प्रश्न का पहला भाग है? इसी से संबंधित मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि

अगर कोई अधिकारी या कोई विभाग एक्सपेंशन या उसके कारण हुए कॉस्ट ओवररन के लिए जिम्मेदार पाया जाता है तो क्या मंत्री महोदय ने उसकी जांच की है और कोई कार्यवाही की है, यह मेरा पहला प्रश्न है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, जब कोई प्रोजैक्ट डेफर किया जाता है तो उसके कई कारण होते हैं जैसे खाद का है तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखकर उसको डेफर किया जाता है। यह स्वाभाविक है कि जब डेफर होता है तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। जो अभी डेफर किए गए हैं वे इसलिए किए गए हैं क्योंकि डिमांड नहीं है और सप्लाई के लिहाज से भी हम सैल्फ सफीशिएंट हो गए हैं, इसलिए वे डेफर किए गए हैं। लेकिन नामरूप का जो प्रोजैक्ट है इसका तो प्रोडक्शन ही इस साल में शुरू हो जाने वाला है। कैबिनेट कमेटी ने सभी पहलुओं को मद्देनज़र रखकर उसको दोबारा एप्रूवल दी है कि उसका एक्सपेंशन हो। कुछ इन्क्वायरीज़ हर प्रोजैक्ट में होती हैं। उसके लिए अगर कुछ स्पेसेफिक डिटेल माननीय सदस्य चाहते हों तो मैं वह डिटेल उनको दे सकता हूं। लेकिन यह कुदरती है कि उसमें कुछ छानबीन होती है। उसको देखा जाता है। उसके बाद उसको एप्रूवल दी जाती है।

श्री रामदास अग्रवाल: सभापति महोदय, यह मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी नहीं है। मैं पहले प्रश्न का ही क्लैरीफिकेशन चाहता हूं और वह यह है कि स्टैंडिंग कमेटी ने स्वयं जो रिमार्क दिया है, वह मैं पढ़ रहा हूं:

> "The Committee are unhappy to note that there has been both cost and time overun in the revamp of HFC, Namrup."

सभापति महोदय, सारे पी.एस.यूज. की कहानी यहीं आकर अटकती है। हर पी.एस.यू. के अंदर टाइम ओवररन होता है कॉस्ट ओवररन होता है। फिर डिमांड-सप्लाई का प्रश्न आ जाता है और उनके प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाती है जिसके कारण एक्सचैकर को उसका पेमेंट करना पड़ता है या गवर्नमेंट को बजटरी सपोर्ट करना पड़ता है। तो कहीं पर आकर कम-से-कम कोई विभाग इस बात की जांच करे कि किस को अकाउंटेबल बनाया जाए। यह तो कम-से-कम तय होना चाहिए। हम तो हर बार उसी कहानी को रिपीट करते हैं, बताते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इस कारण इस देश के हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है जिस पर हम लीपा-पोती करके जवाब देते हैं पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आखिर अगर एच.एफ.सी. के इस प्लांट में डिले हुआ और 234 करोड़ के बजाय अब 509 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है तो उसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए?

श्री सुखदेव ढिंडसा: सर, कारण तो मैंने बताए हैं। चेंज ऑफ स्कोप है, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ी थी। अब ये दो-तीन महीने में प्रोडक्शन शुरू कर देगा।

श्री रामदास अग्रवाल: वह शुरू तो हो जाएगा, लेकिन कॉस्ट ओवररन तो 300 करोड़ रुपए पड़ गया है।

श्री सभापति: श्री शंकरराव चव्हाण।

श्री रामदास अग्रवाल: सर , मेरा सैकंड सप्लीमेंटरी...

श्री सभापति: नहीं, हो गया है।

SHRI S.B. CHAVAN: Mr. Chairman, Sir, it is a very strange kind of reply that the hon. Minister was pleased to give on the floor of the House, that the capacity of a running plant is not fully utilised because of the fact that the demand and supply positon is not very favourable. It is not understandable at all. We cannot understand it. We cannot understand the kind of explanation which the hon. Minister is giving. I think, it is deliberate thing. If I may say so, the capacity of the public sector units and the Government-run units are not being fully utilised because some of the officers are more interested in import of fertilizer; and, in order to achieve that objective, they are doing like this. This is a deliberate sort of thing, which goes on.

Another thing on which I would like to have information from the hon. Minister is about the total requirement of the country as a whole. What is the requirement of urea? What is the requirement of diammonium phosphate? How much we were able to produce and how much we were importing? Is there any plan in this respect? For the Tenth Plan, you are saying that it is only the private sector that can go ahead. But is there any plan by which the existing plants can be expanded in order to see that our requirement of fetilizers is met from indigenous production, both public and private?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर , मेरा ख्याल है कि यह तो एक्सपेंशन का सवाल था। उस प्लांट को एक्सपेंड करना था और वह हो रहा है। इसलिए वह कैपेसिटी जो पहले है, वह अंडर-यूटिलाइजेशन नहीं है।

श्री शंकरराव चव्हाण: यह एक्सपेंशन शुरू करने से पहले तय करना होता है, काम शुरू होने से पहले डिमांड के ऊपर आप उसे रोक नहीं सकते।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर , यह पहली दफा हुआ है। पिछले साल एक भी बोरी नहीं उगाहनी पड़ी। हम सेल्फ-सफीसिएंट हैं, लेकिन आगे प्रोजेक्ट करने के लिए एक्सपेंशन हुआ है। इसके अलावा ओमान के साथ हमारा समझौता हुआ है। वहां साढ़े 16 लाख टन का प्रोडक्शन होगा और सन् 2005 में वह आ जाएगा। इसलिए मेरी समझ में इस कमी की हमें आवश्यकता नजर नहीं आ रही है।

SHRI K. M. SAIFULLAH: I would like to know from the hon. Minister one thing. In Andhra Pradesh, there is one fertilizer plant, the Ramagundam Fertilizer Plant. It has become sick. The Chief Minister of Andhra Pradesh has written so many letters to the Central Government for its revival. But nothing has been done People in the country are of the opinion that all the proposals sent by Shri Chandrababu Naidu will be expedited. But our work is not being done. It is a very important project for us. I would like to know from the hon. Minister as to what the latest position is.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, कुछ ऐसे प्लांट हैं, जिनको हमने पैकेज भी दिए हैं। बीआईएफआर ने कहा, तो हमने, गवर्नमेंट ने पैकेज दिए, फिर भी प्लांट नहीं चला। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और बीआईएफआर ने भी कहा कि चूंकि यह चल नहीं सकता इसलिए इसको बंद होना चाहिए इसलिए वह बंद हुआ। सर, दो बार इसकी स्टडी करवाई गई, सारा देखा गया, लेकिन वह वाइबल बनता ही नहीं था और इसलिए उसके बंद करने का काम किया गया।

SHRI K. M. SAIFULLAH: Sir, our Chief Minister has written a detailed letter to you stating that it can be revived. I do not know whether the hon. Minister has seen that letter or not. I would request the hon. Minister to look into it.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, हम इसको ग्रुप आफ मिनिस्टर्स में भी देख रहे हैं। इन्होंने जैसा कहा, आनरेबिल मुख्यमंत्री जी का पत्र हमारे पास आया है। उस पर भी ग्रुप आफ मिनिस्टर्स में विचार कर रहे हैं।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Sir, in this regard, we met the hon. Prime Minister a number of times. The Prime Minister had given us an assurance that he would look into the matter, positively, in the interest of the workers. My humble request, through you, Sir, to the Minister is that, he should look into that letter once again and see whether the Ramagundam Fertilizer Plant can be revived.

श्री सुखेदव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, मैं, यही कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही यह ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनाया है, जो इस प्रोजेक्ट के साथ और दूसरे प्रोजेक्टस पर भी विचार कर रहा है। ग्रुप आफ मिनिस्टर्स जो भी फैसला करेगा, उस पर हम कार्यवाही करेंगे।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, we have brought, probably, three Calling Attentions on this particular issue. It is not a question of the Ramagundam Fertilizer Plant alone. नीतीश जी, बरौनी भी है। Durgapur, Haldia; these units are also there. For the last eight years, these are under the BIFR, and I am sorry to say, the hon. Minister is not correct in his perception that the BIFR decides

whether it is viable or not. Only when you tell me, as a promoter, whether I can run this company, the economic viability will be assessed by the BIFR. The Government has not said 'Yes'or 'no'. All the Units are under shut down. But look at the point. Here, it is stated that so far as the Tenth Five Year Plan is concerned, बात गई सो गई। उस वक्त तो पुराने थे मंत्री, अब तीन-चार साल से नए-नए मंत्री आ गए हैं। अब तो नाइंथ फाइव ईयर प्लान की बात छोड़ दीजिए। Look at the reply. What are the plants which are coming up in the Tenth Five Year Plan? So far as fertilizer is concerned, अंडर इंपलीमेंटेशन करके आप कहें, एक यूरिया प्लांट 3.8 लाख का आ रहा है? Should this country presume that during the next ten years, in the Tenth Plan आप जो फर्टिलाइजर की डिमांड बता रहे हैं, डिमांड घट गई है? वह तो हर चीज की डिमांड घटी है, स्टील की डिमांड भी घटी है। वही तो एक प्रोब्लम है। इकोनोमिक पालिसी, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डिमांड घटी है तो क्या अगले पांच साल तक देश में यूरिया की डिमांड नहीं होगी? और, अगर होगी तो इन पांच साल की डिमांड के लिए आप क्या करेंगे? How will you prepare? जब आपको यह 30 लाख इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्या तभी आप देखेंगे कि यूरिया कहां गया? We will again wake up. Today, there is nothing in the Tenth Plan. No new fertilizer plants are coming up. I would request that if the old fertilizer plants are revived and expanded, they would cost less. Then, why are you sitting on this Fertilizer Corporation of India and the Hindustan Fertilizer Corporation of India? To say that the Ramagundam Fertilizer Plant cannot be run means, it requires certain brain. Here, Mr. Murli Manohar Joshi is sitting; he knows all this. Time and again, it has been said that these are all coal-based fertilizer factories. But forty per cent fertilizer factories running in China are coal- based. We are talking about China day in and day out. I am fed up. I would not like to bring even a Calling Attention again. Look at the functioning of the Hindustan Fertilizer Corporation in the whole eastern zone. Sir, I tell you about my State, West Bengal. We are the sixth largest consumer of urea, but there is not a single urea plant in my State! Can this country run like this? I do not blame the Minister. It is the Prime Minister. If he has some time off from the Temple and the Masjid, he can concentrate on other issues! Mr. Nitish Kumar is here. इसके लिए कितने ही सालों से लड़ रहे हैं। क्या इसका कोई फैसला भी होगा? Yes, here, we will decide whether we require fertilizers or not. The Judiciary will decide कि मंदिर कहां बनेगा, मस्जिद कहां बनेगी? अगर वह यही तय करता रहेगा तो देश में पार्लियामेंट की जरूरत क्या है? I demand, Sir, that the Minister or the Prime Minister should come out specifically आपको फर्टिलाइजर प्लांट देश में चलाना है या नहीं चलाना है? पांच साल के बाद फर्टिलाइजर इम्पोर्ट नहीं होगा, आप अगर यह एसोरेन्स आज माननीय सदन में दे दें तो हम लोग इसके बारे में दूसरी बात सोच सकते हैं, Otherwise, the Government is bound to revive it.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा। .....(**व्यवधान**).....

श्री संघ प्रिय गौतम: पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है? .....(**व्यवधान**).....

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह बंगाल की बात नहीं है। आपकी यह सोच है, आप संसद में हंसी-मजाक बना रहे हैं। नीतीश जी, आप क्यों नहीं खड़े हो जाते? यह बंगाल की बात नहीं है।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: नहीं, कोई बंगाल की बात नहीं है। सर, माननीय सदस्य की जो शंका है वह भी मैं दूर करना चाहता हूँ। जैसा मैंने कहा, ओमान में जो 2005 में शुरू हो जाएगा .....(**व्यवधान**).....

श्री दीपांकर मुखर्जी: हमारा फर्टिलाइजर बंद होगा और ओमान में जो फर्टिलाइजर बनेगा वह हम यहां लाएंगे। इससे क्या लोगों को नौकरी मिलेगी?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: आप मेरा जवाब तो सुनिए। .....(**व्यवधान**).....

श्री दीपांकर मुखर्जी: आप ओमान की बात करने लगे, कहां गया स्वदेशी! .....(**व्यवधान**)..... ओमान से फर्टिलाइजर आएगा, हमारे फर्टिलाइजर के कारखाने बंद रहेंगे? .....(**व्यवधान**).....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: इसके अलावा .....(**व्यवधान**).....

श्री दीपांकर मुखर्जी: ओमान से क्यों मंगाएंगे आप? .....(**व्यवधान**).....

श्री जीवन राय: पहले हमारे जो हैं, जो हिन्दुस्तान की जमीन पर हैं, उनको रिवाइव कीजिए। .....(**व्यवधान**) .....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: देखिए, उनके लिए मैंने पहले कहा है, जो इन्होंने नाम लिए हैं उनके लिए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बना है। हमने उस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है और मीटिंग्स चल रही हैं—दो मीटिंग्स हो गई हैं, तीसरी मीटिंग .....(**व्यवधान**).....

श्री जीवन राय: पांच साल हो गए हैं। दो-तीन दफा इस हाऊस में ऐश्योरेंस भी हुआ कि हम पूरा रिवाइव करेंगे। .....(**व्यवधान**)..... आप तो खड़े हो जाते हैं। .....(**व्यवधान**).....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: अगर आप जवाब नहीं सुनना चाहते तो ठीक है।.....(**व्यवधान**)..... तीन महीने हुए ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बने। .....(**व्यवधान**).....

श्री दीपांकर मुखर्जी: यह ग्रुप आफ मिनिस्टर्स सैकिंड टाइम बना है। कांग्रेस के टाइम पर भी बना था ग्रुप आफ मिनिस्टर्स, उसने डिसाइड क्यों नहीं किया था? आप एक ग्रुप आफ मिनिस्टर और बनाइए, फिर यह अदल-बदल होगा, फिर एक और ग्रुप आफ मिनिस्टर्स बनेगा और फर्टिलाइज़र का दाम गिरता चला जाएगा। Pipelines are falling down in this plan. I have seen this in the Ramagundam plant. सर, यह क्या हो रहा है? जब तक ग्रुप आफ मिनिस्टर्स नहीं बनेगा, क्या ये बैठे रहेंगे? .....(**व्यवधान**).....

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, यह किस तरह से बात कर रहे हैं, इनको ऐसे बात करने का अधिकार किसने दे दिया? .....**(व्यवधान)**..... आप शालीनता से बात करें।

श्री दीपांकर मुखर्जी: आपने उत्तर प्रदेश में गोरखपुर फर्टिलाइज़र देखा है?

श्री नरेन्द्र मोहन: हां, मैंने उसको देखा है।

श्री दीपांकर मुखर्जी: क्या हालत है उसकी, उसको चलाना है या नहीं?

श्री नरेन्द्र मोहन: आप आराम से बात कीजिए न।

श्री दीपांकर मुखर्जी: ठीक है, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूं कि आप उसे चलवा दीजिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, सिर्फ वही नहीं है , इन प्रिंसिपल चार प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं जो डेफर किए गए, इसलिए कि डिमांड नहीं है। उनमें से दो तो कृभकों के हैं-एक हज़ीरा, गुजरात में है जो 7.68 लाख का है, दूसरा आर.पी.एफ., ठाल का है, वह भी 7.68 लाख का है, तीसरा कृभको का गोरखपुर का है, वही भी इतनी ही केपिसिटी का है और चौथा इफको का नेल्लौर का है, वह भी सेम केपिसिटी का है। ये इन प्रिंसिपल सैंक्शन हुए हैं लेकिन डेफर किए गए हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। .....**(व्यवधान)**.....

श्री जीवन राय: ये बहुत पहले इन प्रिंसिपल सैंक्शन हो गए थे। .....**(व्यवधान)**..... इन प्रिंसिपल और टैक्निकल? .....**(व्यवधान)**.....

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: इन प्रिंसिपल। हमने मंगाया नहीं है, हमने कोई इम्पोर्ट नहीं किया है। **(व्यवधान)** उसके लिए प्रोजेक्ट तैयार है। **(व्यवधान)** in principle, this project was sanctioned in 1995. सर, यहां पार्लियामेंट में आने का फायदा क्या है .....**(व्यवधान)**... In 1995, it was passed in principle. Seven years have already passed. It was agreed in 1995. ..**(व्यवधान)**... हमारे लिए यह पार्लियामेंट ही मंदिर-मस्जिद है।

SHRI RAMACHANDRA KHUNTIA: Sir, while we are discussing about the new fertilizer plants, I would like to know from the hon. Minister whether he is aware of the fact that the Talcher fertilizer plant office has been closed by the Government. On the other hand, the Government has given money to two coalbased factories in other States in order to rehabilitate these two factories. I would like to know whether the Government has also any plan to restart the Talcher fertilizer plant immediately and rehabilitate the workers.

Secondly, the Paradeep Phosphate Factory has been privatised. Now what are the conditionalities of the contract? I would like to know whether they have

finalised rules and regulations for the workers keeping in view the interests of the workers.

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति जी, जहां तक वर्कर्स का सवाल है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसको देख रहा है लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि वर्कर्स के इंट्रस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और उस इंट्रस्ट को कायम रखा जाएगा.....(**व्यवधान**)

श्री रामचन्द्र खूंटिया: बिहार में, आंध्र में, ये फैक्ट्रियां चलती हैं लेकिन उड़ीसा में क्यों बंद हैं? ....(**व्यवधान**) महोदय, उड़ीसा की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई लेकिन same type of factories बिहार में, आंध्र में, चलती हैं क्योंकि उन लोगों को जरूरत है मगर उड़ीसा की फैक्ट्रियां बंद हैं, क्यों?

कृषि मंत्री (श्री अजीत सिंह): बिहार वाली भी बंद है।

श्री रामचन्द्र खूंटिया: तो उन्हें भी चलाइए, बिहार में भी चलनी चाहिए, बिहार में फैक्टरी चलती हैं तो अच्छा है।

श्री रमा शंकर कौशिक: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने इन प्रश्नों का उत्तर यह दिया कि चूंकि डिमांड नहीं है, इसलिए हम ये प्लांट्स बंद कर रहे हैं। यह तो हकीकत है कि इस समय हमारे देश के किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे खाद खरीद सकें लेकिन ऐसा नहीं है कि खाद की आवश्यकता नहीं है, खाद की आवश्यकता है लेकिन पिछले कई वर्षों से उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य तो क्या, लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उसके कारण उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वे खाद खरीद सकें। माननीय चव्हाण साहब ने और माननीय दीपांकर मुखर्जी जी ने जो प्रश्न पूछे हैं, उनका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है। मंत्री जी कृपा करके यह बताएं कि आगे आने वाले दिनों में जब किसानों की हालत कुछ सुधरेगी और जब हमारी आवश्यकता भी बढ़ेगी, उस समय फर्टिलाईजर्स के ये जो प्लांट्स बंद किए गए हैं, क्या उनको चलाने की कोई योजना है? सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाईजर प्लांट्स बंद हैं, बंगाल में बंद है, बिहार में बंद हैं। नए प्लांट लगाने की बात तो छोड़िए लेकिन जो प्लांट अभी बंद पड़े हैं, उनको सुधारने के लिए आपके पास क्या योजना है?

श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सभापति महोदय, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो प्लांट बंद हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उनको देख रहा है। उसकी एक आखिरी मीटिंग अभी होने है, उसके बाद उस पर बहुत जल्दी रिपोर्ट आएगी। जहां तक स्टॉक का सवाल है, उसको भी हम हर 3 महीने के बाद देखते हैं। पालिसी मैटर के तहत हमने इसको इसीलिए डैफर किया है कि जब जरूरत पड़ेगी, तब हम शुरू कर देंगे। इससे किसानों को खाद की कोई कमी नहीं होगी।

*182. [*The Questioners (Shri Abani Roy and Shri Prem Chand Gupta) were absent. For answer vide page 24 infra.*]